

236

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

संख्या—

/XVIII(II)/2015

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 30 जून, 2015

विषय—मै0 हैरिटेज बिल्डवैल प्रा0लि0, नई दिल्ली को ग्राम डाण्डा लखौण्ड, आमवाला, उपराला, तहसील एवं जनपद देहरादून में कुल 4.4247 है0 भूमि के उपयोग की अवधि में समय विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-912/भूकय/XVIII(II)/2008 दिनांक 22.08.2008 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 हैरिटेज बिल्डवैल प्रा0लि0, नई दिल्ली को ग्राम डाण्डा लखौण्ड, आमवाला उपराला, आमवाला तहसील एवं जनपद देहरादून में उक्त शासनादेशों में वर्णित प्रयोजन हेतु कुल 4.4247 है0 भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154 की उपधारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 06 माह के लिए निम्न शर्तों के साथ बढ़ायी जाती है :-

1. यदि क्रेता क्रय किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
2. भूमि का उपयोग वर्तमान में प्रचलित महायोजना के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. भू-क्षेत्र में नियोजन दृष्टि से आवश्यक न्यूनतम 24 मीटर पहुंच मार्ग की सम्बद्धता कराने के उपरान्त ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा क्षेत्र में मौलिक अवस्थापना सुविधायें भी सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. नाले-खाले एवं निचली भूमि होने पर जल की निकासी इस प्रकार की जायेगी कि महायोजना के अनुसार भूमि पर किये जा रहे निर्माण पर किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा का प्रभाव न पड़े तथा नाले-खाले की भूमि पर कोई निर्माण अर्थात् नाले-खाले पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करते हुए इसके दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा इसे प्रोजेक्ट का भाग बनाते हुए जल की निकासी इस प्रकार की जायेगी, जिससे निर्मित भवन प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से सुरक्षित रहें।

Sd/-

5. निर्माण से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
 6. सम्बन्धित बिल्डर भूमि क्रय के उपरान्त प्रचलित महायोजना के अनुसार ही निर्माण कार्य करायेंगे। प्रश्नगत स्थल पर आवास विभाग/सम्बन्धित प्राधिकरण की प्रचलित भवन उपविधियां एवं समय-समय पर तत्सम्बन्धी निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा तथा शासनादेश सं०-2269/V/आ०-2007-55(आ०)/2006 टी०सी० दि०-06.11.2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. आवास विभाग के अन्तर्गत कलस्टर, नेवरहुड एवं टाउनशिप के विकास हेतु निर्गत मार्गनिर्देशिका विषयक शासनादेश सं०-1942/V-अ-20067115(आ०)/06 दि०-17.08.2007 एवं उक्त के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं प्राधिकरण की बिल्डिंग बाईलॉज का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
 8. भूमि का विक्रय अनुमन्य नहीं होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।
 9. योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
 10. उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 2- अतः इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं इस आदेश के अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-¹⁷⁰² (1)/XVIII(II)/2015 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, श्री संजीव वोहरा, मै० हैरिटेज बिल्डवैल प्रा० लि०, डी-29 तृतीय तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली।
5. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Edw
(भास्करानन्द)
सचिव।